

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2013—चैत्र 13, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-19/2013/वाक. (पं.)/पांच (26).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-75/2006/वाक. (पं.)/पांच (62) दिनांक 05-07-2006 को अधिक्रमित करते हुये, किसी भूमि स्वामी अथवा रेवेन्यू बुक सरकुलर IV-3-10 के अधीन पट्टाधारी व्यक्ति के द्वारा, कृषि प्रयोजनार्थ बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु निष्पादित बंधक विलेखों, आडमान विलेखों तथा बंधक संपत्ति पर अतिरिक्त भार के विलेखों पर, प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है.

इस अधिसूचना में :—

(क) “बैंक” से अभिप्रेत है :—

(एक) दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 (क्र. 10 सन् 1949) में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी,

(दो) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 (क्र. 23 सन् 1955) के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,

(तीन) दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सब्सिडीयरी बैंक्स) एक्ट 1959 (क्र. 38 सन् 1959) में यथा परिभाषित सब्सिडीयरी बैंक,

(चार) दि बैंकिंग कम्पनीज (एक्जीजीशन तथा ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970 (क्र. 5 सन् 1971) के अधीन गठित तत्स्थानी नवीन बैंक,

(पांच) दि एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स कार्पोरेशन एक्ट 1963 (क्र. 10 सन् 1963) के अधीन गठित दि एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन,

- (छः) दि छत्तीसगढ़ एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन, रायपुर,
- (सात) दि कम्पनीज एक्ट, 1956 (क्र. 1 सन् 1956) के अधीन निगमित एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड,
- (आठ) रीजनल रूरल बैंक एक्ट, 1976 (क्र. 21 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक,
- (नौ) छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1999 (क्र. 20 सन् 2000) की धारा 2 के खण्ड (ख), (ग) एवं (ङ) के अन्तर्गत पंजीकृत विकास बैंक,
- (दस) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 2 के खण्ड (डी-एक) के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी बैंक,

(ख) “कृषि प्रयोजन” से अभिप्रेत है :—

भूमि को खेती योग्य बनाना, भूमि पर खेती करना, भूमि का विकास, जिसमें सिंचाई के स्रोतों का विकास सम्मिलित है, फसलें उगाना एवं उनकी कटाई, उद्यान, कृषि वन विज्ञान, रोपण तथा कृषि कर्म, पशु अभिजनन, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, बीज कृषि, मत्स्यपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, शूकर पालन एवं कुक्कुट पालन और किसी भी ऐसे क्रियाकलाप के संबंधों में उपकरणों तथा मशीनरी (ट्रक, मिनी ट्रक, जीप, मेटाडोर एवं ट्रिलिंग मशीन को छोड़कर) का अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-19/2013/वाक. (पं.)/पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2013/वाक. (पं.)/पांच (26), दिनांक 03-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 3rd April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-19/2013/CT(R)/V (26).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 11 of 1899), in supersession of this Department's Notification No. F 10-75/2006/CT(R)/V (62) dated 05-07-2006 the State Government hereby exempts the stamp duty chargeable on deeds of mortgage, hypothecation and deeds of further charge on mortgaged property, executed by a bhumiswami or a person holding land as pattadhari under Revenue Book Circular IV-3-10 in favour of bank for securing loans for agricultural purposes.

Explanation—In this Notification :—

(a) “Bank” means :—

- (i) a banking company defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949);
- (ii) the State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (No. 23 of 1955);

- (iii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959);
 - (iv) a corresponding new bank, constituted under the Banking companies (Acquisition, Transfer of undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1971);
 - (v) the Agricultural Refinance and Development Corporation constituted under the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (No. 10 of 1963);
 - (vi) the Chhattisgarh State Agro-Industries Development Corporation Ltd. Raipur;
 - (vii) agricultural Finance Corporation Ltd. a company incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 10 of 1956);
 - (viii) a Regional Rural Bank established under sub-section (1) of section 3 of Regional Rural Bank Act, 1976 (No. 21 of 1976);
 - (ix) a Development Bank within the meaning of clause (b), (c) and (e) of Section 2 of the Chhattisgarh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam 1999 (No. 20 of 2000) of the said Act.
 - (x) a registered sahakari Bank within the meaning of clause (d-1) of Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Society Act, 1960 (No. 17 of 1961) of the said Act.
- (b) **“Agricultural purposes” means :—**
making land fit for cultivation of land, improvement of land including development of sources of irrigation, raising and harvesting of crops horticulture, forestry, planting and forming, cattle breeding, animal husbandry, dairy farming, seed farming, apiculture, pisciculture, sericulture, piggery and poultry farm farming and the acquisition of implements and machinery (excluding Truck, Mini Truck, Jeep, Matador and Drilling Machine) in connection with any such activity.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2013/वाक. (पं.)/पांच (27).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, उच्च शिक्षा प्रयोजनार्थ बैंकों से प्राप्त होने वाले शिक्षा ऋण के लिए बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधक विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-20/2013/वाक. (पं.)/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-20/2013/वाक. (पं.)/पांच (27), दिनांक 03-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 3rd April 2013

NOTIFICATION

No. F 10-20/2013/CT(R)/V (27).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby exempts the stamp duty, chargeable on instruments of mortgage executed in favour of banks for obtaining educational loan for the purpose of Higher education.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.